(b) the total number of towns in the country, State-wise, which have no proper drainage system; and

(c) the number of towns State-wise, proposed to be provided with drinking water and proper drainage during the year 1974-75 and during the Fifth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA): (a) and (b). The available information is given in the Statement laid on the Table of the House [*Placed in Library See* No. LT-6860/74].

(c) The information about physical targets to be covered during the Fifth Five Year Plan are not available. The information about the targetted coverage during 1974-75 available from a few States has also been indicated in the annexure.

पिछड़े हुए राज्य, जिनका खाद्यान्नों की ढुलाई तथा रख रखाव का व्यय केन्द्रीय सरकार वहन करती

8638. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे पिछड़े राज्यों के नाम क्या है, जिनके खाद्यान्नों के ढोने तथा रख रखाव पर आने वाले व्यय को केन्द्रीय सरकार वहन करती है और गत तीन वर्षों में प्रति क्विंटल वार्षिक व्यय कितना रहा है ;

(ख) इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम की प्रति क्विंटल व्यय की दर कितनी रही है ; और

(ग) क्या इन राज्यों के खाद्यान्नों की ढुलाई तथा रखरखाव का प्रबन्ध भी भारतीय खाद्य निगम को दिया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) : (क) से (ग). मौजूदा प्रबन्धों के अधीन केन्द्रीय स्टाक से राज्य सरकारों को खाद्यान्न भारतीय निगम के डिपों पर या गन्तव्य स्थान तक रेल पर निःशुल्क भार के समान निगम मूल्यों पर दिये जाते है। क्योंकि भारतीय खाद्य निगम केन्द्रीय सरकार के खाते में खाद्यान्न सप्लाई करने के लिये जिम्मेदार है, इसलिये केन्द्रीय पूल से दिए गए जाने वाले खाद्यान्नों की ढुलाई और उनके भण्डारण का खर्च केन्द्रीय सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकारें राज्य के अन्दर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए जिम्मेदार है और इसलिये राज्य सरकारों या उनकी एजेंसियों को भारतीय खाद्य निगम के डिपो या रेल छोर गन्तव्य स्थानों से स्टाक के प्राप्त होने के बाद भण्डारण और ढुलाई पर अतिरिक्त खर्च और अन्य प्रासंगिक खर्च करना पड़ता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1970–71 से 1972–73 के तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के खाते में खाद्यान्नों की ढुलाई और भण्डारण पर किया गया औसत खर्च इस प्रकार है –

वर्ष	ढुलाई खर्च	(रु० प्रति क्विंटल) भण्डारण खर्च
1970–71	3 47	1.01
1971–72	3 96	1 32
1972–73	3 48	1.15